नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 173
दि. 28.03.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महंगाई पर अस्थायी ब्रेक: सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, तेल कंपनियों को राहत, उपभोक्ताओं को फिलहाल स्थिर कीमतों का सहारा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इस कदम का उद्देश्य सीधे तौर पर आम जनता को राहत देना नहीं, बल्कि तेल कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करना है, ताकि फिलहाल ईंधन की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जा सके। यानी उपभोक्ताओं को तत्काल राहत कीमत घटने के रूप में नहीं, बल्कि कीमतें स्थिर रहने के रूप में मिलेगी।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने भारतीय तेल कंपनियों की स्थिति को गंभीर बना दिया था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस भारी वृद्धि के चलते सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 24 रुपये और डीजल पर करीब 30 रुपये प्रति लीटर तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार के सामने दो ही विकल्प थे—या तो यह पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाए, जिससे महंगाई और बढ़े, या फिर सरकार खुद इस वित्तीय दबाव को अपने ऊपर ले।

सरकार ने दूसरा विकल्प चुना और एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर तेल कंपनियों को राहत देने का रास्ता अपनाया। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर प्रभावी उत्पाद शुल्क घटकर 11.9 रुपये प्रति लीटर रह गया है, जिसमें मूल उत्पाद शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क, कृषि उपकर और सड़क बुनियादी ढांचा उपकर शामिल हैं। वहीं, डीजल पर यह प्रभावी शुल्क 7.80 रुपये प्रति लीटर रह गया है।

इस कटौती से तेल कंपनियों को अपने नुकसान की भरपाई करने में कुछ मदद मिलेगी और वे फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी से बच सकती हैं। हालांकि, इस फैसले का एक बड़ा आर्थिक असर भी है। सरकार को इस कदम के चलते सालाना करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा। यह एक बड़ा वित्तीय बोझ है, लेकिन सरकार ने इसे आम जनता को महंगाई के झटके से बचाने के लिए जरूरी माना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक तरह से 'शॉक एब्जॉर्बर' की तरह काम करेगा, जिससे वैश्विक बाजार की मार सीधे उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचेगी। इसी के साथ सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर भी शुल्क लगा दिया है। डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यात के कारण होने वाली आपूर्ति की कमी को रोकना है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें ज्यादा होती हैं, तो कंपनियां निर्यात को प्राथमिकता देती हैं, जिससे घरेलू बाजार प्रभावित हो सकता है। सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है।

इस बीच, निजी क्षेत्र की कंपनी Nayara Energy पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है। नायरा के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है, जबकि डीजल भी 90 रुपये से ऊपर बिक रहा है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, जो बाजार के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखती हैं, ने अभी तक कीमतों को स्थिर बनाए रखा है। यह स्थिति सरकार के हस्तक्षेप के कारण ही संभव हो पाई है। अगर कीमतों के गणित को समझें, तो कच्चे तेल की कीमत में हर एक डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से पेट्रोल और डीजल की लागत लगभग 50 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाती है। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमत में करीब 30 डॉलर की वृद्धि हुई है, जिससे ईंधन की लागत में 15 से 18 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि तेल कंपनियों पर रोजाना करीब 2,400 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था।

सरकार की यह रणनीति फिलहाल स्थिति को संभालने में मददगार जरूर है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है और कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं, तो अंततः इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यदि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव जारी रहता है, तो वैश्विक तेल बाजार में और उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। यह बैठक डिजिटल माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके संभावित प्रभावों पर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य 'टीम इंडिया' की भावना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना था, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि 'लॉकडाउन' जैसी किसी भी संभावना को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। वैश्विक स्तर पर भी ईंधन की कीमतों में तेजी देखी जा रही है—दक्षिण-पूर्व एशिया में 30 से 50 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका में करीब 30 प्रतिशत, यूरोप में 20 प्रतिशत और अफ्रीका में 50 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ चुकी हैं।

कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम एक संतुलित रणनीति का हिस्सा है, जिसमें उपभोक्ताओं को तत्काल महंगाई के झटके से बचाने के साथ-साथ तेल कंपनियों को भी सहारा दिया गया है। हालांकि, आने वाले समय में वैश्विक परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं, यह तय करेगा कि यह राहत कितने समय तक टिकाऊ रह पाएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि आम जनता को ईंधन की बढ़ती कीमतों से कुछ समय के लिए राहत मिली है और बाजार में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश जारी है।

बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज: तृणमूल के खिलाफ भाजपा का 'आरोपपत्र' जारी करेंगे अमित शाह

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अमित शाह शनिवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का बहुप्रतीक्षित 'आरोपपत्र' जारी करने जा रहे हैं। भाजपा की यह रणनीति सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को घेरने और जनता के बीच उसकी छवि को चुनौती देने की मंशा से जुड़ी मानी जा रही है।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, यह 'आरोपपत्र' केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि पिछले लगभग 15 वर्षों में टीएमसी सरकार के कार्यकाल की कथित कमियों और विफलताओं का विस्तृत लेखा-जोखा होगा। पार्टी का उद्देश्य है कि वह इन मुद्दों को जनता के सामने इस तरह रखे कि चुनावी बहस का केंद्र शासन की उपलब्धियों के बजाय उसकी कमजोरियां बन जाएं। इस कदम को भाजपा के आक्रामक चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है।

बताया जा रहा है कि इस 'अभियोगनामा' में कुल 14 प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है, जिनके आधार पर टीएमसी सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी है। इनमें भ्रष्टाचार के आरोप, कानून-व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और

स्वास्थ्य सेवाओं की हालत जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं। भाजपा का दावा है कि इन सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है।

भाजपा नेताओं का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, जिनसे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष लगातार टीएमसी पर निशाना साधता रहा है। महिला सुरक्षा का मुद्दा भी चुनावी विमर्श में प्रमुख स्थान रखता है, और भाजपा इसे लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुधार की कमी को भी पार्टी अपने आरोपपत्र का अहम हिस्सा बनाने जा रही है।

इस पूरे अभियान की खास बात यह है कि भाजपा केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इसके बाद वह अपने 'संकल्प पत्र' के जरिए इन समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करेगी। पार्टी का उद्देश्य यह दिखाना है कि वह न केवल वर्तमान सरकार की कमियों को उजागर कर रही है, बल्कि एक वैकल्पिक और बेहतर शासन मॉडल भी पेश करने के लिए तैयार है। इससे मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि बदलाव केवल आलोचना नहीं, बल्कि ठोस योजनाओं के साथ आएगा।

अमित शाह पिछले कुछ महीनों में कई बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं और पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटे हैं। भाजपा की रणनीति स्पष्ट है—राज्य के हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ना। शाह के दौरे और बैठकों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और चुनावी मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय करना है।

राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दो चरणों में—23 और 29 अप्रैल—को प्रस्तावित है। ऐसे में चुनावी तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। टीएमसी जहां अपने शासन की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है, वहीं भाजपा आरोपों के जरिए सरकार को घेरने और सत्ता परिवर्तन का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधाराओं और विकास के मॉडल के बीच भी मुकाबला बन चुका है। भाजपा का आरोपपत्र इस संघर्ष को और तीखा बना सकता है, क्योंकि इससे चुनावी बहस का केंद्र सीधे तौर पर सरकार की नीतियों और उनके परिणामों पर आ जाएगा। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। आरोप-प्रत्यारोप, वादे और जवाबी हमलों के बीच जनता के सामने कई सवाल खड़े होंगे, जिनका जवाब उन्हें मतदान के जरिए देना होगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का यह 'आरोपपत्र' कितना असर डालता है और क्या यह चुनावी समीकरणों को बदलने में सफल हो पाता है या नहीं।

खून का रिश्ता बना साजिश का जाल: महिला पुलिसकर्मी ने पिता को मिल्कशेक में जहर देकर की हत्या, तीन साल बाद खुला सनसनीखेज राज

(जीएनएस)। नई दिल्ली। रिश्तों की बुनियाद जहां विश्वास और अपनत्व पर टिकी होती है, वहीं जब वही रिश्ते साजिश और धोखे में बदल जाएं तो घटना न केवल दिल दहला देती है, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख देती है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटी—जो खुद कानून की रक्षक है—पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा है। तीन साल तक एक सामान्य मौत समझी जाने वाली घटना अब एक सोची-समझी हत्या के रूप में सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे से लेकर आम लोगों तक सभी को हैरान कर दिया है।

यह मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से जुड़ा है, जहां 25 अप्रैल 2023 की सुबह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। उस दिन महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी जयंत बल्लावर अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। घर का माहौल सामान्य था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक भयावह घटना घटने वाली है।

सुबह के समय उनकी बेटी आर्या बल्लावर, जो खुद एक सेवारत महिला पुलिसकर्मी है, ने उन्हें एक मिल्कशेक दिया। पिता ने बिना किसी संदेह के उसे पी लिया और अपने काम के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के प्रशासनिक भवन तक पहुंचे, उन्हें अचानक चक्कर आने लगे। कुछ ही पलों में वे जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी—जयंत बल्लावर की मौत हो चुकी थी। उस समय इस घटना को एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या या अचानक हुई बीमारी के रूप में दर्ज किया गया। न तो परिवार और न ही पुलिस को किसी प्रकार की साजिश का संदेह हुआ। पोस्टमार्टम और शुरुआती जांच में भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले, जिसके कारण मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला गया और फाइल बंद कर दी गई। तीन साल तक यह मामला एक सामान्य मौत के रूप में ही दर्ज रहा। लेकिन समय के साथ सच्चाई छिपी नहीं रह सकी। तीन साल बाद, जब पुलिस ने इस मामले की दोबारा जांच शुरू की, तो जो तथ्य सामने आए, उन्होंने सभी को स्तब्ध कर दिया। जांच में पता चला कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आर्या बल्लावर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया।

जांच के दौरान सामने आया कि आर्या बल्लावर का 2022 से आशीष शेडमाके नामक युवक के साथ प्रेम संबंध था। लेकिन उनके पिता जयंत बल्लावर इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। पारिवारिक असहमति धीरे-धीरे एक बड़े विवाद में बदल गई, जिसने अंततः एक भयावह साजिश का रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार, आर्या और आशीष ने इस "रुकावट" को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया।

इस योजना को अंजाम देने के लिए आर्या ने अपने चचेरे भाई चैतन्य गेदम से संपर्क किया और उसे जहर लाने के लिए 5,000 रुपये दिए। जांच में यह भी सामने आया कि एक चौथा व्यक्ति, जिसकी पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है, ने इस जहर की व्यवस्था की। इस तरह चार लोगों ने मिलकर एक सोची-समझी साजिश रची और उसे अंजाम दिया।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का तरीका बेहद साधारण लेकिन खतरनाक था—मिल्कशेक में जहर मिलाकर दिया गया, जिससे किसी को भी तुरंत शक नहीं हुआ। यही कारण था कि शुरुआती जांच में इसे एक सामान्य मौत माना गया और मामला बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में जब कुछ संदेहास्पद तथ्य सामने आए और पुलिस ने गहराई से जांच की, तो पूरा सच उजागर हो गया।

यह मामला केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत इच्छाएं और भावनाएं रिश्तों पर भारी पड़ जाती हैं। एक बेटी द्वारा अपने ही पिता की हत्या की साजिश रचना समाज के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करता है—क्या आधुनिक जीवनशैली और बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच पारिवारिक संबंध कमजोर होते जा रहे हैं?

पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि साजिश कितने समय से रची जा रही थी और इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकता है। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि जहर कहां से और कैसे प्राप्त किया गया।

इस घटना ने पुलिस विभाग को भी आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि इसमें शामिल मुख्य आरोपी खुद एक पुलिसकर्मी है। कानून की रक्षा करने वाली जब खुद कानून तोड़ने लगे, तो यह व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन जाती है।

फिलहाल, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेशी की प्रक्रिया जारी है। आने वाले समय में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है—यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि रिश्तों में विश्वास और संवाद की कमी किस हद तक विनाशकारी साबित हो सकती है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का सख्त ऐलान: अमेरिका-इजरायल और उनके सहयोगियों के लिए रास्ता बंद, वैश्विक व्यापार पर गहराया संकट

(जीएनएस)। तेहरान। पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के शक्तिशाली अर्धसैनिक संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने ऐलान किया है कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य अब अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी देशों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस फैसले ने न केवल क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार के सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। आईआरजीसी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन देशों और उनके समर्थकों के बंदरगाहों से आने-जाने वाले किसी भी जहाज को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पोतों के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की जाएगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब पहले से ही इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो चुका है और खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता चरम पर है।

आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने इस प्रतिबंध को लागू करते हुए तीन कंटेनर पोतों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 'सेपाह न्यूज' के अनुसार, ये पोत होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरानी नौसेना की चेतावनी के बाद उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। यह घटना इस बात का संकेत है कि ईरान अपने फैसले को सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उसे जमीन पर सख्ती से लागू भी कर रहा है।

इस घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू यह

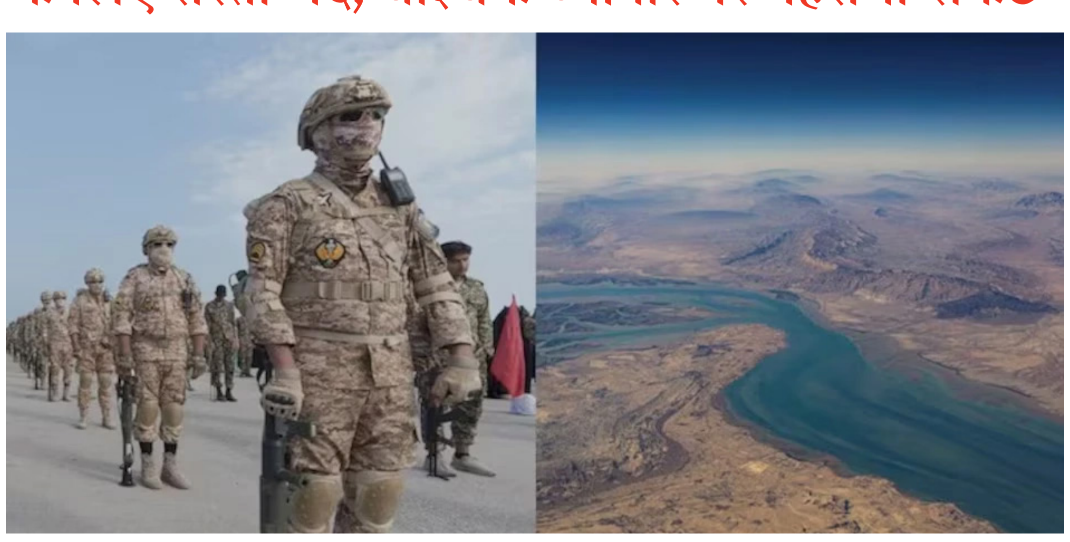

भी सामने आया है कि जिन तीन पोतों को वापस भेजा गया, उनमें से दो चीन की प्रमुख शिपिंग कंपनी 'कॉस्को' से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऊर्जा बाजार से संबंधित जानकारी देने वाली कंपनी केप्लवर के अनुसार, ये दोनों पोत ईरान के तट के पास इस संकरे जलमार्ग को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये पोत 28 फरवरी को शुरू हुए मौजूदा संघर्ष के बाद से ही खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए थे और अब सुरक्षित रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे थे।

होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के कुल तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग का बंद होना वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए गंभीर झटका साबित हो सकता है। तेल की कीमतों में भारी उछाल, आपूर्ति में बाधा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता जैसी आशंकाएं अब और प्रबल हो गई हैं।

ईरान का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को एक 'रणनीतिक हथियार' की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अपने विरोधियों को आर्थिक और सैन्य दोनों स्तरों पर चुनौती दी जा सके। हालांकि, इस कदम से वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया भी तेज हो सकती है, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।

इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दावा किया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला हुआ है और वहां से जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। लेकिन आईआरजीसी के ताजा दावे और पोतों को वापस लौटाने की घटनाओं ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जमीनी स्थिति और राजनीतिक बयानों के बीच बड़ा अंतर हो सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस की आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा का असर सीधे तौर पर दुनिया भर के देशों पर पड़ेगा, खासकर उन देशों पर जो ऊर्जा के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर आता है।

कुल मिलाकर, होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का ईरान का फैसला एक बड़ा भू-राजनीतिक संकेत है, जो यह दर्शाता है कि यह संघर्ष अब सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर भी फैल चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को कैसे संभालता है और क्या कूटनीतिक प्रयास इस बढ़ते संकट को कम कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल, हालात यही संकेत दे रहे हैं कि तनाव कम होने के बजाय और गहराने वाला है।

संपादकीय

गैरजरूरी खींचतान में फंसे पंजाब-हिमाचल

सही मायनों में पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में सीमा प्रवेश शुल्क को लेकर जारी विवाद ने देश के संघीय ढांचे में व्याप्त एक गहरी खामी को ही उजागर किया है। जो बताता है कि देश के राज्यों की राजस्व जरूरतों तथा अंतर्राज्यीय आवागमन के सिद्धांतों के बीच टकराव के कारण मौजूद हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश फिलहाल वित्तीय संकट की चुनौती से रूबरू है। उसने अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर राज्य में प्रवेश करने का शुल्क लगभग दोगुना करने का निर्णय लिया है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश ने यह फैसला अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए लिया था। लेकिन यह वित्तीय फैसला बाद में हिमाचल प्रदेश व पंजाब में राजनीतिक व आर्थिक विवाद का रूप ले चुका है। यही वजह है इस फैसले से ज्यादा प्रभावित राज्य पंजाब ने भी हिमाचल प्रदेश के वाहनों पर ऐसे ही कर बढ़ाने की धमकी दे दी है। वास्तव में हिमाचल सरकार का यह फैसला दूरगामी दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है। यह सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक हद तक पर्यटन उद्योग पर ही निर्भर है। ऐसे में इस कदम का राज्य के पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। यह बढ़ाया गया प्रवेश शुल्क पर्यटकों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। खासकर पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाले कम बजट के साथ यात्रा पर निकले पर्यटकों के लिये, जो कि सप्ताहांत में आने वाले पर्यटकों का एक बड़ा हिस्सा है। निस्संदेह, इस फैसले से ऐसे पर्यटक हतोत्साहित हो सकते हैं। इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि मौजूदा प्रतिस्पर्धी पर्यटन के परिदृश्य में टैक्स बढ़ाए जाने पर पर्यटक वैकल्पिक पहाड़ी पर्यटक स्थलों की ओर रुख कर सकते हैं। राज्य द्वारा बाद में इस कर-वृद्धि के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लेना, निश्चित रूप से इस मुद्दे की आर्थिक संवेदनशीलता को ही दर्शाता है।

यह भी एक हकीकत है कि दो राज्यों के बीच लिए गए कर बढ़ाने के ऐसे फैसलों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत होनी चाहिए। यह जानते हुए कि हिमाचल प्रदेश गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है, पंजाब की प्रतिक्रिया संवेदनशील ढंग से सामने आनी चाहिए थी। ऐसे में पंजाब की हिमाचल की तर्ज पर कर बढ़ाने की चेतावनी प्रतिशोधात्मक नीति पर चलने के अप्रिय फैसले को ही उजागर करती है। इस तरह की बदले में कर लगाने की नीति राजनीतिक दृष्टि से भले ही सुविधाजनक लगती हो, लेकिन आम लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे निर्णय से दैनिक यात्रियों, परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों और छोटे व्यवसायियों की आवाजाही बाधित हो सकती है। इनकी यात्रा की सुगमता सीमा पार सुचारू आवागमन पर निर्भर करती है। निर्विवाद रूप से दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय गलियारे व्यापार, श्रम गतिशीलता और क्षेत्रीय एकीकरण की जीवन रेखा के पर्याय होते हैं। यदि हम व्यापक स्तर पर इस समस्या को देखें तो यह घटनाक्रम देश के संघवाद की भावना पर भी प्रश्न उठाता है। यह एक हकीकत है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ढांचे द्वारा समर्थित हमारी आर्थिकी की संरचना का लक्ष्य आंतरिक व्यापार बाधाओं को कम करना है। दूसरे अर्थों में देखें कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर असमान रूप से लक्षित करके अतिरिक्त प्रवेश-कर लगाना, इस उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। जो अतीत की उस दोषपूर्ण 'चेक पोस्ट' अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकती है, जो तमाम विसंगतियों को लिए हुए थी। निर्विवाद रूप से ऐसे मामलों में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होगी। यदि राज्य का राजस्व वृद्धि ही लक्ष्य है तो इसके लिये तर्कसंगत टोल प्रणाली को अपनाना होगा। वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के रखरखाव से जुड़े लक्षित उपयोगकर्ता शुल्क जैसे विकल्पों पर भी विचार करना होगा। साथ ही अंतर्राज्यीय संबंधों को टकराव की बजाय संवाद के माध्यम से सुलझाने की जरूरत है। वह भी तब जब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र और पंजाब के मैदानी इलाके आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हैं। पड़ोसी को साझेदार की बजाय राजस्व स्रोत के रूप में देखने की प्रवृत्ति दोनों के लिये नुकसान दायक साबित होगी।

संगीत में पुराने दौर की गरिमा लौटाने का वक्त

> फिल्मी गीतों में हमेशा प्रेम, आकर्षण व अंतरंगता जैसे विषयों को भी गहरे प्रतीकों व गरिमा के साथ पेश किया गया है। किंतु मौजूदा दौर में, खासकर रैप व व्यावसायिक संगीत के बढ़ते प्रभाव के चलते वह नाजुक संतुलन गड़बड़ा रहा है। बंदूकें, धन और ताकत का प्रदर्शन करने वाले संगीत के वीडियो भले रोमांचक लगते हों, लेकिन नयी पीढ़ी पर उनका गलत असर हो रहा है।

भारतीय फ़िल्मी गाने कभी भी महज मनोरंजन का साधन नहीं रहे हैं; उन्होंने हमेशा समाज की भावनात्मक गहराई, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और परिष्कृत सौंदर्यबोध को प्रतिबिम्बित किया। एक समय था जब हिंदी सिनेमा ने प्रेम, आकर्षण और शारीरिक अंतरंगता जैसे विषयों को भी असाधारण गरिमा से प्रस्तुत किया था। बोल विचारोत्तेजक होते हुए भी संयमित, अभिव्यक्ति करते वक्त गरिमामय रहते थे। किंतु, वर्तमान दौर में, विशेषकर रैप व व्यावसायिक संगीत के बढ़ते प्रभाव के चलते वह नाज़ुक संतुलन अब लुप्तप्राय है; उसकी जगह उघड़ी कामुकता और सनसनी की प्रवृत्ति ने ले ली है।

नोरा फ़तेही के नृत्य-गीत 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर हाल ही में खड़ा हुआ विवाद इसी बदलाव का एक उदाहरण है। इस गाने की इसके कथित अश्लील बोलों और बेहद कामुक प्रस्तुति के लिए आलोचना हुई। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों, अनौपचारिक बैठकों व बहस के मंचों पर जनाक्रोश दिखा। बताया जाता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन जैसे प्राधिकरणों ने वकील विनीत जिंदल की शिकायत के बाद मामले का संज्ञान लिया, मानवाधिकार आयोग ने भी इस बारे नोटिस जारी किया।

बादशाह के 'टटीरी' गीत मामले में भी कुछ ऐसा ही हंगामा देखने को मिला था। इस हरियाणवी रैप गाने का इसके बोलों और दृश्यों को लेकर व्यापक विरोध हुआ, जिन्हें अश्लील और स्त्री को बतौर वस्तु प्रस्तुत करने वाला माना गया। इसके बाद कानूनी शिकायतें दर्ज की गईं, और हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कलाकार को स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया, पेश न होने पर कड़े निर्देश जारी किए, जिनमें गिरफ़्तारी, पासपोर्ट ज़ब्ती और राज्य में उसकी प्रस्तुतियों पर रोक लगाना शामिल था। मामला और तूल पकड़ गया, जब एक एफआईआर में गाने की सामग्री अश्लील बतायी गयी-खासकर वे दृश्य जिनमें स्कूल जैसे माहौल में अनुचित चित्रण किया गया था। अंततः, बढ़ते विरोध के दबाव में इस गाने को वापस लिया और माफ़ीनामा भी जारी किया। इस घटना ने जो बड़ा सवाल खड़ा किया कि कलात्मक आजादी व सामाजिक ज़िम्मेदारी के बीच सीमा रेखा कहां खींची जाए-वो अभी अनुत्तरित है। ये घटनाएं कोई अलग-थलग मामले नहीं; बल्कि समकालीन संगीत जगत में एक व्यापक चलन की ओर संकेत करती हैं। अनेक आधुनिक गाने अब 'सभ्य रुचि' की सीमाएं लांघते प्रतीत होते हैं; इनमें ऐसी भाषा व दृश्यों का प्रयोग किया जाता है जो श्रोताओं के बड़े वर्ग को भोंडे व असहज करने वाले लगते हैं। ऐसी भाव-भंगिमाएं या अभिव्यक्तियां जो खुलेआम अश्लील इशारे करती हैं, या व्यक्तियों को महज़ वस्तु के रूप में पेश करती हैं, ये उस ज़हीन और गरिमामय रोमांस के चित्रण की जगह ले रहे हैं, जो कभी फ़िल्मी संगीत की पहचान था। ऐसे बोल अक्सर भावनात्मक जुड़ाव पेश करने के बजाय, रोबदार छवि और खोखले दिखावे के भाव ही अधिक परिलक्षित करते हैं।

ऐसी सामग्री की बढ़ती लोकप्रियता शायद सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। म्यूज़िक वीडियो में अक्सर हिंसा, आक्रामकता और वस्तुवाद-बंदूकें, लक्ज़री कारें और शक्ति-प्रदर्शन-जैसे दृश्य अधिक रखे जाते हैं। कुछ खास वर्ग में, जिनमें पंजाबी पॉप और रैप शामिल हैं, दबदबे और मर्दानगी के बार-बार दोहराए जाने वाले विषयवस्तु ही हावी रहते हैं। जहां ये चीज़ें तुरंत आकर्षित करती हैं और जोश भर सकती हैं वहीं इनसे सांस्कृतिक सोच बदलने का खतरा रहता है-खासकर उन संवेदनशील युवाओं में, जो इन छवियों को तेज़ी से अपनाते हैं।

रचनात्मक स्वतंत्रता कलात्मक अभिव्यक्ति की नींव है और इसका सम्मान होना चाहिए। हालांकि, यह पहचान रखना भी उतना ही अहम है कि दीर्घकालीन कलात्मकता अक्सर कल्पनाशीलता, भाषा और संयम के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण से उभरती है। जब गूढ़ता की जगह उघड़ापन आता है, तो अभिव्यक्ति की सौंदर्यपरक गुणवत्ता कम होने लगती है। पिछले दशकों के गीतों पर नज़र डालने से एक स्पष्ट अंतर दिखता है। तब भी, प्रेम, विरह और शारीरिक अंतरंगता के विषय ही मुख्य थे, फिर भी उन्हें शालीनता और काव्य-सौंदर्य के साथ व्यक्त किया जाता था। 'आज साजन मोहे अंग लगा लो' या 'पिया अंग लग लग के भई सांवली मैं' जैसी पंक्तियां स्पष्टतया सामीप्य की इच्छा व्यक्त करती हैं, लेकिन ऐसा वे गरिमा और संगीतमयता के साथ करती हैं। इसी तरह, 'शरारत करने को ललचाये रे मेरा मन' गाना चंचलता भरी चाहत को बिना अश्लीलता की सीमा पार किए व्यक्त करता है।

रोमांस की और भी गहरी प्रत्यक्ष अभिव्यक्तियों को भी नफ़ासत से गढ़ा गया था। श्रोता स्पष्टता की बजाय अपरोक्ष संकेतों के माध्यम से अंतरंगता को महसूसता है, जिससे कल्पना को पूरी तस्वीर बनाने का अवसर मिलता है। कालजयी गीत 'बांहों में चले आओ' (मजरूह सुल्तानपुरी) पर भी विचार करें, जो उकसाने के बजाय गर्मजोशी और स्नेह के साथ निकटता का निमंत्रण है। या फिर भावपूर्ण गीत 'रात अकेली है, बुझ गए दीये...' जो सौम्य अंतरंगता का माहौल रचता है। ऐसी रचनाएं दर्शाती हैं कि भावनात्मक गहराई और गरिमा कैसे एक साथ हो सकती हैं। पुराने गीतों की रचना में रूपकों ने अहम भूमिका निभाई। 'मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी' जैसी अभिव्यक्तियां काव्य-समृद्धि के साथ विरह को व्यक्त करती हैं, जबकि 'तेरे लबों को चूम लूं मैं' जैसी पंक्तियां स्पष्टतः उत्तेजक होते हुए भी परिष्कृत रहती हैं।

महत्वपूर्ण यह है कि जवानी और चाहत के विषयवस्तु वाले गीत-'चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी', या 'आज मैं जवान हो गई हूं'-एक नाजुक संतुलन बनाए रखते थे। उनका चंचल अंदाज़ और काव्यात्मक आवरण यकीनी बनाता था कि अभिव्यक्ति अभद्रता के स्तर तक न गिरे। हालांकि, यह कहना गलत होगा कि आधुनिक संगीत में परिष्कृतता नहीं है। कई समकालीन रचनाएं सूक्ष्म प्रेम की परंपरा को कायम रखती हैं। 'पहला नशा', 'तुम ही हो', 'रातां लम्बियां', 'केसरिया' और 'तेरा बन जाऊंगा' जैसे गीत दर्शाते हैं कि श्रोता आज भी संजीदगी, मधुरता और भावनात्मक प्रामाणिकता पसंद करते हैं।

आजकल के कई गीतों को लेकर गहरी चिंता सिर्फ उनकी शब्दावली से नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत जीवनदर्शन में भी निहित है। पैसा, आक्रामकता और वस्तुकरण पर बार-बार ज़ोर देने से ऐसे मूल्यों के सामान्यीकरण का खतरा रहता है। जब संगीत सफलता के सतही प्रतीकों-चमकदार जीवनशैली, प्रभुत्व बनाने व शक्ति प्रदर्शन-का महिमामंडन करता हो, तो यह अनजाने में आकांक्षाओं व सामाजिक व्यवहार पर असर डाल सकता है।

सिनेमा और संगीत का समाज के साथ हमेशा एक गतिशील संबंध रहा। ये दोनों ही प्रचलित रुझानों को प्रतिबिंबित करते हैं और उन्हें आकार देते हैं। इसलिए, यह सवाल वाजिब है कि क्या तुरत-फुरत लोकप्रियता और वायरल सफलता की चाहत कलात्मक गरिमा व सांस्कृतिक संवेदनशीलता की कीमत पर होनी चाहिए। अंततः, इस चर्चा का उद्देश्य निंदा नहीं, बल्कि चिंतन करना है। मंतव्य उस दौर को याद करना है जब फिल्मी संगीत में रोमांस, चंचलता और काव्यात्मक सौंदर्य का संतुलन था, बिना अश्लीलता का सहारा लिए। वह विरासत आज भी रचनाकारों के लिए मूल्यवान मार्गदर्शक है। शायद आज कलात्मकता की नए सिरे से सराहना करने की जरूरत है-जहां रूपक, कल्पना और भाषाई शालीनता फिर से प्रेम और मानवीय भावनाओं के चित्रण को समृद्ध करें। जब यह संतुलन बहाल होगा, तब भारतीय फिल्मी गीत उस शाश्वत आकर्षण को बनाए रखते हुए विकसित होते रह सकते हैं जिसने उन्हें कभी चिरस्थायी सांस्कृतिक धरोहर बनाया था।

प्रेरणा

खामोशी का अनुशासन: सफलता की अदृश्य सीढ़ी

वृंदावन की शांत गलियों में एक दिन एक युवा अपने मन की बेचैनी लिए संत प्रद्युम्न जी के पास पहुँचा। उसकी आँखों में सफलता के सपने थे, लेकिन मन में असमंजस और अस्थिरता भी थी। उसने विनम्र होकर संत के चरण स्पर्श किए और कहा कि वह जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, पर उसे कोई ऐसा उपाय चाहिए जो उसके मार्ग को स्पष्ट कर दे। संत ने उसे ध्यान से देखा, एक ताबीज दिया और कहा कि यदि जीवन में सचमुच सफल होना है, तो एक बात हमेशा याद रखो—पैर फिसल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। इसके लिए खामोशी को अपना साथी बनाना सीखो, क्योंकि मौन ही क्रोध का सबसे प्रभावी उपचार है।

यह साधारण सा वाक्य उस युवक के जीवन का आधार बन गया। दरअसल, खामोशी को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि यह सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जब इंसान अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, तो वह अपने जीवन को भी दिशा देने लगता है। आज के समय में, जहाँ हर कोई अपनी बात कहने की जल्दी में रहता है, वहीं जो व्यक्ति मौन का महत्व समझता है, वही भीड़ से अलग नजर आता है।

खामोशी का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ का प्रतीक है। यह वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने का प्रयास करता है। कई बार हम आवेश में आकर ऐसे शब्द कह देते हैं, जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है और बाद में पछतावा ही हाथ आता है। अगर उसी क्षण हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ, खुद को शांत कर लें, तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है।

जीवन में सफलता पाने के लिए केवल ज्ञान या संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मानसिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है। खामोशी हमें यही संतुलन प्रदान करती है। जब हम शांत रहते हैं, तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह हमें जल्दबाजी में गलत कदम उठाने से रोकती है और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

खामोशी हमें सहनशीलता भी सिखाती है। जब कोई हमारे खिलाफ कुछ कहता है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हमारा पहला स्वाभाविक प्रतिक्रिया देने का होता है। लेकिन यदि हम उस समय मौन रहकर स्थिति को स्वीकार करें और समझें, तो हम पाएंगे कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। समय के साथ सच अपने आप सामने आ जाता है और हमारी खामोशी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।

आज के डिजिटल युग में, जहाँ हर व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी राय तुरंत व्यक्त कर देता है, वहाँ खामोशी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना सोचे-समझे कही गई बातें न केवल विवाद को जन्म देती हैं, बल्कि व्यक्ति की छवि को भी प्रभावित करती हैं। जो लोग संयम और धैर्य के साथ अपनी बात रखते हैं, वही समाज में सम्मान पाते हैं और लंबे समय तक प्रभाव छोड़ते हैं।

खामोशी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सुनने की क्षमता प्रदान करती है। जब हम कम बोलते हैं, तो हम दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुन पाते हैं। इससे हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं और हमारी समझ का दायरा बढ़ता है। एक सफल व्यक्ति वही होता है, जो केवल अपनी बात कहने में ही नहीं, बल्कि दूसरों की बात समझने में भी सक्षम हो।

यह भी सच है कि हर स्थिति में चुप रहना सही नहीं होता। कई बार हमें अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी पड़ती है, लेकिन फर्क यह है कि हम कैसे और कब बोलते हैं। यदि हम सोच-समझकर और संयम के साथ बोलते हैं, तो हमारे शब्दों का प्रभाव अधिक होता है। वहीं बिना सोचे-समझे बोले गए शब्द हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।

खामोशी एक अभ्यास है, जिसे धीरे-धीरे अपने जीवन में उतारा जा सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, क्योंकि मन बार-बार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो यह हमारी आदत बन जाती है और हमें भीतर से एक अलग ही शांति का अनुभव होता है।

अंततः, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति का भी प्रतिबिंब होती है। यदि हमारा मन शांत और स्थिर है, तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। खामोशी हमें यही आंतरिक शक्ति प्रदान करती है।

संत प्रद्युम्न जी की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी पहले थी। उन्होंने जो सरल सा संदेश दिया, वह जीवन का गहन सत्य है। यदि हम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख लें और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें, तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता।

इसलिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए खामोशी को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब आप अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आप अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जाने लगते हैं। यही खामोशी का अनुशासन है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाकर सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचाता है।

जलवायु परिवर्तन: भविष्य नहीं वर्तमान का महाविनाशकारी संकट

आज मानव सभ्यता जिस सबसे बड़े संकट के सामने खड़ी है, वह युद्ध, महामारी या आर्थिक मंदी नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन है। दुनिया आज जलवायु संकट के ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां हर नया आंकड़ा खतरे की घंटी बनकर सामने आ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताजा रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि 2015-2025 का दशक अब तक का सबसे गर्म दौर रहा है। यह केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि पृथ्वी के बदलते स्वभाव का गंभीर संकेत है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रीनहाउस गैसों का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है और पृथ्वी का एनर्जी इम्बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। महासागर, जो जलवायु संतुलन के सबसे बड़े नियंत्रक माने जाते हैं, अब 90 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त गर्मी सोख रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि पृथ्वी का तापमान केवल हवा में ही नहीं, जल और भूमि के भीतर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन अब धीरे-धीरे आने वाली समस्या नहीं रही, बल्कि यह वर्तमान का संकट बन चुका है। दुनिया के अनेक हिस्सों में असामान्य गर्मी, बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगल की आग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्रति का संतुलन बिगड़ रहा है और मौसम का मिजाज अनिश्चित होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ रही है तो कहीं महीनों तक बारिश नहीं हो रही। यह असंतुलन सीधे-सीधे मानव जीवन, कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इस बदलते मौसम ने सबसे ज्यादा मनुष्य के स्वास्थ्य पर हमला किया है। भारत के संदर्भ में यह संकट और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के अनेक शहरों में तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पहले 45 डिग्री को ही अत्यधिक गर्मी माना जाता था। अब असामान्य गर्मी ने फरवरी और मार्च जैसे महीनों को भी झुलसाना शुरू कर दिया है। हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। इसका असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि बिजली, पानी, खेती, श्रम, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी ने केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि वन्यजीव, पेड़-पौधे और सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को भी संकट में डाल दिया है। जलवायु परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा कारण मानव का विकास मॉडल है। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगीकरण और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पृथ्वी को लगातार गर्म कर रहा है। आज वैश्विक तापमान लगभग एक लाख 25 हजार वर्षों के उच्चतम स्तर के आसपास पहुंच चुका है। यह स्थिति बताती है कि समस्या प्रकृति में नहीं, बल्कि मानव की जीवनशैली और विकास की दिशा में है।

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां इस संकट को और अधिक खतरनाक बना रही हैं। दुनिया के अनेक हिस्सों में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। युद्ध केवल मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को ही नष्ट नहीं करते, बल्कि पर्यावरण को भी गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक, रसायन, धातु, ईंधन और आग से वातावरण में भारी मात्रा में जहरीली गैसें फैलती हैं। तेल भंडारों में आग, रासायनिक संयंत्रों का नष्ट होना और सैन्य गतिविधियां वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कई गुना बढ़ा देती हैं। इस प्रकार युद्ध और जलवायु परिवर्तन मिलकर पृथ्वी को दोहरे संकट की ओर धकेल रहे हैं। भारत सहित दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत जिले किसी न किसी जलवायु जोखिम के दायरे में आ चुके हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। दूसरी ओर समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। यदि समुद्र स्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले दशकों में तटीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है। यह केवल पर्यावरण संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी बन सकता है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कटौती नहीं की गई, तो तापमान के नए-नए रिकॉर्ड टूटते रहेंगे और पृथ्वी रहने योग्य स्थान कम होती जाएगी। जल संकट, खाद्य संकट, स्वास्थ्य संकट और प्रवासन जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। दुनिया के अनेक वैज्ञानिक अब चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं किया गया, तो पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ सकता है। लेकिन इस संकट में ही अवसर भी छिपा हुआ है। यह समय विकास मॉडल को बदलने का है। ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। शहरों को कंक्रीट के जंगल बनाने के बजाय हरित शहर बनाना होगा। जल प्रबंधन को जन आंदोलन बनाना होगा। वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और नदियों के संरक्षण पर गंभीरता से काम करना होगा। कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना होगा, कम पानी वाली फसलों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। साथ ही जिला स्तर पर हीट एक्शन प्लान, जल संरक्षण योजना, वृक्षारोपण अभियान और स्थानीय पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम लागू करने होंगे। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई केवल सरकारें नहीं जीत सकतीं, इसके लिए समाज, उद्योग, वैज्ञानिक और आम नागरिक सभी को मिलकर काम करना होगा।

दुनिया की महाशक्तियों के लिए यह समय सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। यदि वे केवल आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति की दौड़ में ही उलझी रहीं और पृथ्वी के भविष्य की चिंता नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्हें यह समझना होगा कि पृथ्वी बचेगी तो अर्थव्यवस्था भी बचेगी, मानव सभ्यता भी बचेगी और विकास भी बचेगा। यदि पृथ्वी ही तपती और असंतुलित हो गई, तो सारी प्रगति बेकार हो जाएगी। आज आवश्यकता है कि दुनिया की महाशक्तियां कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कठोर और बाध्यकारी नीतियां बनाएं, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करें, वनों की कटाई रोकें और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें।

अभियान

रामराज्य का शाश्वत संदेश: मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन की अनंत प्रेरणा

भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे आदर्श हैं जो समय, परिस्थितियों और युगों की सीमाओं से परे जाकर सदैव मानवता को दिशा देते रहे हैं। इन्हीं में सबसे उज्ज्वल और प्रेरणादायक स्वरूप हैं भगवान श्रीराम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, कर्तव्य, त्याग, प्रेम, न्याय और अनुशासन का जीवंत उदाहरण है। हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी को पूरे भारतवर्ष में रामनवमी अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जाती है। यह दिन केवल एक जन्मोत्सव नहीं, बल्कि उस आदर्श जीवन-दर्शन का उत्सव है जिसे श्रीराम ने अपने आचरण से स्थापित किया।

इस वर्ष रामनवमी की तिथि को लेकर लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति भी बनी, क्योंकि पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च को प्रारंभ होकर 27 मार्च तक रही। ऐसे में सामान्य श्रद्धालु 26 मार्च को यह पर्व मनाते हैं, जबकि वैष्णव परंपरा के अनुयायी उदया तिथि के आधार पर 27 मार्च को रामनवमी मनाते हैं। तिथि का यह अंतर भले ही गणना का विषय हो, लेकिन श्रद्धा का भाव दोनों ही दिनों में समान रूप से प्रकट होता है।

रामनवमी के दिन अयोध्या का वातावरण अद्भुत हो उठता है। हजारों-लाखों श्रद्धालु देश के कोने-कोने से यहां पहुंचते हैं। सरयू नदी में स्नान कर भक्त पंचकोसी परिक्रमा करते हैं और प्रभु के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। पूरी अयोध्या राममय हो जाती है, जहां हर ओर भजन-कीर्तन, अखंड रामायण पाठ और जय श्रीराम के उद्घोष गूंजते रहते हैं। यह दृश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और आस्था की गहराई का प्रतीक होता है।

श्रीराम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहां हुआ था। उनका जीवन प्रारंभ से ही आदर्शों की नींव पर खड़ा था। वे न केवल एक आज्ञाकारी पुत्र थे, बल्कि एक आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श राजा भी थे। उनका हर निर्णय धर्म और मर्यादा के अनुरूप होता था, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े।

उनकी उदारता और करुणा का उदाहरण अहिल्या उद्धार की घटना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अहिल्या को जब समाज ने ठुकरा दिया, तब श्रीराम ने उसे सम्मान दिया और उसका उद्धार किया। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह संदेश है कि समाज द्वारा तिरस्कृत व्यक्ति को भी अपनाने और सम्मान देने का साहस ही सच्ची महानता है।

इसी प्रकार केवट के प्रति उनका व्यवहार भी अद्वितीय था। एक साधारण नाविक के प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर श्रीराम ने उसे अपना भाई मान लिया। यह दर्शाता है कि उनके लिए जाति, वर्ग या स्थिति का कोई महत्व नहीं था, बल्कि केवल भाव और श्रद्धा ही महत्वपूर्ण थी। यही कारण है कि उनका जीवन सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया। शबरी के झूठे बेर खाना भी उनके प्रेम और समानता के भाव का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कभी भी बाहरी आडंबरों को महत्व नहीं दिया, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि रखा। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल सच्चे हृदय से होकर जाता है।

श्रीराम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनका वनवास है। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी देने का वचन मांगा, तब दशरथ गहरे धर्मसंकट में पड़ गए। लेकिन जैसे ही श्रीराम को इस वचन का पता चला, उन्होंने बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने न केवल अपने पिता के वचन की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें कर्तव्य को सर्वोपरि रखा जाए।

वनवास के दौरान उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। यह यात्रा केवल कठिनाइयों से भरी नहीं थी, बल्कि यह जीवन के अनेक सत्य और अनुभवों से भी भरी थी। चित्रकूट, पंचवटी और अन्य स्थानों पर उन्होंने जो जीवन जिया, वह साधारण होते हुए भी असाधारण था। पंचवटी में शूर्पणखा की घटना और उसके बाद रावण द्वारा सीता हरण ने कथा को एक नया मोड़ दिया। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह अहंकार, अन्याय और अत्याचार का प्रतीक था। सीता के अपहरण के बाद श्रीराम ने एक सामान्य मनुष्य की तरह दुख व्यक्त किया, जो यह दर्शाता है कि वे भावनाओं से रहित नहीं थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया।

इस दौरान उनकी भेंट हनुमान से हुई, जो उनके सबसे महान भक्त और सहयोगी बने। हनुमान ने न केवल सीता का पता लगाया, बल्कि राम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ मिलकर श्रीराम ने लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया।

यह युद्ध केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष था—एक ओर धर्म, सत्य और न्याय, और दूसरी ओर अधर्म, अहंकार और अन्याय। श्रीराम ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि अंततः सत्य की ही जीत होती है।

रावण का वध करने के बाद भी श्रीराम ने उसके ज्ञान का सम्मान किया। उन्होंने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए भेजा, जो यह दर्शाता है कि वे शत्रु में भी गुणों को पहचानते थे। यह उनके व्यक्तित्व की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद श्रीराम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। उनका शासनकाल, जिसे रामराज्य कहा जाता है, आज भी आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। यह वह समय था जब समाज में न्याय, समानता, शांति और समृद्धि का वातावरण था। कोई भी व्यक्ति दुखी या असंतुष्ट नहीं था। राजा और प्रजा के बीच विश्वास और प्रेम का संबंध था।

रामराज्य केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श है, जिसे आज भी हर समाज प्राप्त करना चाहता है। यह हमें सिखाता है कि यदि शासन में न्याय, पारदर्शिता और करुणा हो, तो समाज में संतुलन और सुख-शांति बनी रह सकती है।

श्रीराम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि महानता चमत्कारों में नहीं, बल्कि साधारण जीवन में असाधारण आचरण में होती है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपने कर्मों से लोगों के दिलों में स्थान बनाया।

आज के समय में, जब समाज अनेक चुनौतियों और नैतिक संकटों का सामना कर रहा है, तब श्रीराम के आदर्श और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, संयम और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।

अंततः, श्रीराम केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवनशैली का प्रतीक हैं। उनके आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण में निहित होती है। यही कारण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम सदैव अनुकरणीय रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते रहेंगे।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच दिया

▸▸ इस विधेयक में विवाह, तलाक, लिव-इन संबंधों तथा विरासती-पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अभूतपूर्व कानूनी रक्षा दी गई

▸▸ गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 के जरिये राज्य के नागरिकों को 'दादा' का समानता का नजराना

▸▸ चैत्री नवरात्रि के मध्य यह विधेयक पारित होने के बाद गुजरात की हर नारी कह सकेगी, "मैं एक नारी हूँ, आधुनिक समय की नारी हूँ, अबला या शक्तिहीन नहीं हूँ, आद्यशक्ति हूँ, अंबिका हूँ !"

(जीएनएस)। गांधीनगर : वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने (मार्च) में जब लोग पूरे वर्ष का लेखा-जोखा करने में व्यस्त थे, तब मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 विधानसभा में प्रस्तुत कर महिलाओं का पुराना ऋण चुकाया, महिलाओं के जीवन से असमानता को दूर किया और समानता का हिसाब पूरा कर दिया।

यह विधेयक पारित कर सरकार ने नारियों के सम्मान को झंकृत करने वाले एक संस्कृत श्लोक का स्मरण कराया।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥

अर्थात् जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ सभी कार्य विफल जाते हैं।

गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पारित कर गुजरात सरकार ने इस श्लोक को चरितार्थ किया और कानूनी संरक्षण देकर नारियों का अभूतपूर्व सम्मान किया है।

गुजरात विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पारित कर राज्य की महिलाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है और इस बात की प्रतीति कराई है कि महिलाओं के जीवन के सभी चरणों में यह सरकार उनके अधिकारों एवं गरिमा की रक्षा करती है तथा यह सरकार किसी भी जाति या धर्म के भेदभाव के बिना सभी महिलाओं को कानूनी संरक्षण देने को कटिबद्ध है।

यह विधेयक प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री ने गुजरात विधानसभा में गर्व से कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार साहब के एक एवं अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का विचार दिया है, वह विचार ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मूल है। यदि देश में समान कानून, विकास के समान अवसर न हों, तो यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' बन ही नहीं सकता। अब विकसित भारत-2047 तक के इस अमृतकाल में देश को समानता का अमृत यूसीसी से देने का प्रधानमंत्री ने संकल्प किया है।"

इस विधेयक में विवाह, तलाक तथा विरासती (पैतृक) संपत्ति जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए, किसी के साथ कोई भी अन्याय न हो; इसे ध्यान में रखकर एक समान कानूनी ढाँचा सुझाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बलपूर्वक कहा था, "यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है; बल्कि समानता, न्याय एवं एकता के राष्ट्रीय संकल्प को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अधिक मजबूत बनाने का हमारा संकल्प है।"

इस विधेयक के जरिये विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, तलाक के लिए समान नियम, पुत्र या पुत्री; सभी को समान विरासती अधिकार के प्रावधान और इन प्रावधानों के पालन के लिए दंड के प्रावधान के साथ इसके कड़े क्रियान्वयन आदि इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

हर धर्म तथा परंपरा के अनुसार हुए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और पंजीकरण न कराने पर दंड का प्रावधान रहेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार के कानून लागू हैं। उनका अध्ययन करके इस विधेयक के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस कानून से किसी धार्मिक विधि तथा परंपरा में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, बल्कि समान नागरिक संहिता केवल कानूनी पहलुओं को नियमित करती है।

गुजरात समान नागरिक संहिता-2026 की महत्वपूर्ण बातें

संविधान की धारा 44 के अनुसार राज्य के लिए सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाने का प्रयास करने का जो प्रावधान है, उसके अनुसंधान में गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के समय-समय पर दिए गए निर्णयों में यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

अनिवार्य विवाह पंजीकरण तथा सजा

इस विधेयक में विवाह के बाद 60 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से विवाह का पंजीकरण कराने का प्रावधान किया गया है। पंजीकरण न करवाने पर 10,000 रुपए तक दंड हो सकता है। जबरन/धमकी/धोखाधड़ी से विवाह करने के मामले में 7 वर्ष तक की सजा तथा एक से अधिक विवाह के मामले में भी 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

अनिवार्य विवाह पंजीकरण से विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है। महिलाओं व बच्चों के अधिकारों की रक्षा होती है। व्यक्ति की वास्तविक वैवाहिक स्थिति दर्ज होती है। इससे गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से होने वाले विवाह के मामलों को टाला जा सकेगा।

तलाक-समानता तथा नियंत्रण

कोर्ट द्वारा तलाक के बाद पंजीकरण अनिवार्य है। कोर्ट से बाहर हुआ तलाक अमान्य रहेगा। कोर्ट से बाहर तलाक लेने के मामले में 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और महिला को किसी भी शर्त के बिना पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया है। अनिवार्य पंजीकरण तथा कोर्ट से मान्यता प्राप्त तलाक प्रक्रिया से धोखाधड़ी, अवैध तलाक तथा झूठी वैवाहिक स्थिति दर्शाने को रोकेगी और भविष्य के विवाहों में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

भरण-पोषण तथा विरासती अधिकार में समानता

सभी धर्मों के लिए भरण-पोषण के समान प्रावधान के कारण महिलाओं को विशेष सुरक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त; समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के पुत्र और पुत्री को समान अधिकार दिया गया है। पुत्र और पुत्री को समान पारिवारिक अधिकार देने से लिंग समानता, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा तथा समाज में न्यायी एवं समान व्यवस्था स्थापित होगी।

लिव-इन संबंधों का नियमन तथा सजा

लिव-इन संबंधों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने पर 3 महीने तक की कैद तथा 10,000 रुपए दंड हो सकता है।

यदि लिव-इन संबंध में रहे व्यक्तियों की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच हो, तो पंजीकरण की जानकारी उनके माता-पिता को दी जाएगी। जबरन/धमकी/धोखाधड़ी से लिव-इन के लिए सहमति लेने के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है। अवयस्क (किशोर) के साथ लिव-इन संबंध में पॉक्सो एक्ट के अनुसार सजा का प्रावधान है। इसके अलावा; पहले से विवाहित होने के बावजूद लिव-इन संबंध में रहने वाले के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान है।

लिव-इन रिलेशनशिप में महिला को कानूनी संरक्षण

इस विधेयक में महिला को भरण-पोषण तथा बच्चे को कानूनी मान्यता दी गई है। पंजीकरण से लिव-इन संबंधों का नियमन करने में मदद मिलेगी। लिव-इन पार्टनर द्वारा त्याग किया जाए, तब महिला को भरण-पोषण मिल सकेगा। लिव-इन संबंध में जन्मे बच्चे के भरण-पोषण, पहचान तथा विरासती अधिकारों का अधिक बेहतर तरीके से संरक्षण हो सकेगा।

समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 तैयार करने के लिए गहनतापूर्वक अध्ययन

समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति द्वारा विभिन्न कानूनों, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के समय-समय पर दिए गए फैसलों और उत्तराखंड राज्य के यूसीसी तथा विश्व के अन्य देशों के इस प्रकार के मॉडल कानूनों का अध्ययन किया गया था और इन सबके निष्कर्ष के रूप में तैयार हुआ गुजरात यूसीसी विधेयक-2026 विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बहुमत से पारित हुआ।

समान नागरिक संहिता-2026 में इन फैसलों को ध्यान में लिया गया

ऐतिहासिक फैसले :

- ▸▸ मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो बेगम (1985)
- ▸▸ सरला मुदगल विरुद्ध भारत सरकार (1995)
- ▸▸ शायराबानो विरुद्ध भारत सरकार व अन्य (2017)
- ▸▸ शबनम हाशमी विरुद्ध भारत सरकार (2014)
- ▸▸ मुमताज आलम विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2023)
- ▸▸ एगनेस विरुद्ध रेजीना थॉमस (2010)
- ▸▸ मायरा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2021)
- ▸▸ अलिया विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (2024) का भी अध्ययन किया गया।

भारतीय कानून :

- ▸▸ हिंदू विवाह अधिनियम 1955
- ▸▸ भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872
- ▸▸ पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936
- ▸▸ विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954
- ▸▸ आनंद विवाह अधिनियम 1909
- ▸▸ आर्य विवाह मान्यता अधिनियम 1937
- ▸▸ मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) क्रियान्वयन अधिनियम 1937
- ▸▸ विदेशी विवाह अधिनियम 1969
- ▸▸ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925
- ▸▸ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- ▸▸ मुस्लिम विवाह विसर्जन अधिनियम 1939
- ▸▸ ईसाई तलाक अधिनियम 1869
- ▸▸ महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005
- ▸▸ बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006
- ▸▸ भारतीय न्याय संहिता 2023
- ▸▸ यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 का अध्ययन किया गया।

भारत के अलावा विश्व के विभिन्न देशों के कानूनों को भी ध्यान में लिया गया

वैश्विक मॉडल

- ▸▸ फ्रेंच सिविल कोड (नेपोलियन कोड) 1804
- ▸▸ जर्मनी बर्गर्लिचेस गेसेट्जबच (बीजीबी) 1900
- ▸▸ तुर्की सिविल कोड 2002
- ▸▸ नेपाल – राष्ट्रीय नागरिक (संहिता) अधिनियम 2017
- ▸▸ अजरबैजान गणतंत्र की परिवार संहिता 1999 का भी अध्ययन किया गया।

गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पारित होने के बाद राज्य की महिलाएँ उनमें मौजूद शक्ति का अनुभव कर सकेंगी तथा हर नारी गरिमामपूर्वक एवं सिर उठाकर कह सकेगी :

बालिका अहं बालिका नव युग जनिता अहं बालिका ।
नाहमबला दुर्बला आदिशक्ति अहमम्बिका ।।

अर्थात् मैं एक नारी हूँ, आधुनिक समय की नारी हूँ, अबला या शक्तिहीन नहीं हूँ, आद्यशक्ति हूँ, अंबिका हूँ।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस) ।श्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09075 मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम स्पेशल को 29 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम–मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 30 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल–कानपुर अनवरगंज स्पेशल को 26 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज – मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 27 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
3. ट्रेन संख्या 09005 बांद्रा टर्मिनस–भिवानी स्पेशल को 29 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09006 भिवानी – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 30 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
4. ट्रेन संख्या 09025 वलसाड – दानापुर स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09026 दानापुर–वलसाड स्पेशल को 30 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
5. ट्रेन संख्या 09031 उधना–हसनपुर रोड अनारक्षित स्पेशल को 28 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09032 हसनपुर रोड–उधना अनारक्षित स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
6. ट्रेन संख्या 09065 सूरत – छपरा स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09066 छपरा–सूरत स्पेशल को 01 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
7. ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद–पटना स्पेशल को 29 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09448 पटना–अहमदाबाद स्पेशल को 01 मई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
8. ट्रेन संख्या 09425 साबरमती–हरिद्वार स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार – साबरमती स्पेशल को 30 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
9. ट्रेन संख्या 09309 इंदौर–हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल को 28 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन 22 एवं 24 मई, 2026 को नहीं चलेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09310 हज़रत निज़ामुद्दीन–इंदौर स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन 23 एवं 25 मई, 2026 को नहीं चलेगी।
10. ट्रेन संख्या 09343 डॉ. अंबेडकर नगर–पटना स्पेशल को 25 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09344 पटना–डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल को 26 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09425 एवं 09309 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 28.03.2026 से प्रारंभ होगी, जबकि ट्रेन संख्या 09075, 09185, 09005, 09025, 09065, 09447 एवं 09343 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 29.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य में पट्टेदारों के लिए खरीद मूल्य भुगतान की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई

किसानों के प्रति मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की विशिष्ट संवेदना

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात गणोत वहिवट (गुजरात पट्टा प्रशासन) तथा कृषि भूमि अधिनियम की धारा 32 अंतर्गत पट्टेदारों के लिए खरीद मूल्य भुगतान करने की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का संवेदनास्पर्शी निर्णय किया है।

गुजरात पट्टा प्रशासन तथा कृषि भूमि अधिनियम 1948 के अनुसार धारा 32जी अंतर्गत किसानों/पट्टेदारों के लिए तहसीलदार तथा कृषि आयोग द्वारा खरीद मूल्य निर्धारित किया जाता है और यह मूल्य कानूनी समयसीमा में भुगतान करना होता है।

पट्टेदारों द्वारा अज्ञानता के कारण खरीद मूल्य का भुगतान न किए जाने के मामले ध्यान में आए हैं। ऐसे मामलों में उन्हें वैध मालिक नहीं माना जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा कृषि भूमि बिक्री, जमीन को गैरकृषि करने के मौकों पर जो मुश्किलें पेश आती हैं, उनका निवारण करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों के हित में समय-समय पर ऐसे खरीद मूल्य भुगतान करने की छूट देकर समयसीमा बढ़ाने के निर्णय किए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने किसानों द्वारा की गई प्रस्तुति तथा 31 दिसंबर 2025 तक के मामलों की शेष संख्या को ध्यान में लेकर किसानों के पक्ष में अधिक नरम रवैया दर्शाते हुए पट्टेदारों को खरीद मूल्य भुगतान करने की अवधि 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

इस किसान हितोन्मुखी निर्णय के फलस्वरूप किसान/पट्टेदार खरीद मूल्य भुगतान कर वैध मालिक बन सकेंगे।

2332 किलो ड्रग्स का रहस्य: 'चूहों ने खा लिया' सरकारी दलील पर उठे बड़े सवाल, CAG रिपोर्ट से मचा हड़कंप

(जीएनएस)। गुजरात। कानून-व्यवस्था और नशा नियंत्रण के मोर्चे पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसने सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में यह सामने आया कि पुलिस हिरासत में रखा गया हजारों किलोग्राम नशीला पदार्थ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जब इस गंभीर मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा गया, तो संबंधित विभाग की ओर से दिया गया जवाब और भी हैरान करने वाला था—कहा गया कि ड्रग्स या तो चूहे खा गए या फिर नमी के कारण उसका वजन कम हो गया। रिपोर्ट के आंकड़े इस पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। अक्टूबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच गुजरात पुलिस ने कुल 6510.54 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया था। नियमानुसार, जब्त किए गए नशे को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाना चाहिए, ताकि उसका दोबारा दुरुपयोग न हो सके। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार केवल 4177.86 किलोग्राम नशीले पदार्थ को ही नष्ट किया गया। इसका मतलब है कि 2332.68 किलोग्राम ड्रग्स—जो कुल जब्ती का लगभग 35 प्रतिशत है—का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है।

जब इस भारी अंतर पर सवाल उठे, तो गृह विभाग ने तीन प्रमुख कारणों का हवाला दिया। पहला, यह कि मालखानों में उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण चूहों और अन्य कीड़ों ने बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को नुकसान पहुंचाया, विशेषकर गांजा जैसी चीजों को। दूसरा, विभाग का कहना था कि जब भांग या अफीम के पौधे जब्त किए जाते हैं, तो उनमें नमी होती है, जो समय के साथ सूख जाती है, जिससे वजन में काफी कमी आ जाती है। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला दावा यह था कि बड़ी मात्रा में गांजा चोरी भी हो गया है। इन दलीलों ने मामले को और संदिग्ध बना दिया है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का गायब होना केवल प्राकृतिक कारणों या चूहों की वजह से संभव नहीं लगता।

ऑपरेशन "रेल प्रहरी" : संवेदनशील मामले में त्वरित कार्यवाही

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा "ऑपरेशन रेल प्रहरी" के अंतर्गत उच्च स्तरीय सतर्कता एवं त्वरित समन्वय के माध्यम से एक नाबालिग लड़की के अपहरण से संबंधित गंभीर प्रकरण का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.03.2026 को वर्सोवा पुलिस स्टेशन, मुंबई में अपराध संख्या 0325/2026, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला पंजीकृत किया गया था। प्राप्त इनपुट के अनुसार, अपहृत नाबालिग को एक युवक द्वारा ट्रेन संख्या 12480 (सूर्यनगरी एक्सप्रेस) के सामान्य श्रेणी कोच में अहमदाबाद की ओर ले जाया जा रहा था।

मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए RPF अहमदाबाद द्वारा तत्काल बहु-स्तरीय निगरानी एवं समन्वित कार्रवाई प्रारंभ की गई। संबंधित संदिग्धों के विवरण एवं फोटोग्राफ का त्वरित प्रसारण कर सभी बीट स्टाफ को अलर्ट किया गया तथा वायरलेस संचार माध्यमों के जरिए सतत निगरानी सुनिश्चित की गई।

ट्रेन के अहमदाबाद स्टेशन पर आगमन के पश्चात निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल, अहमदाबाद श्री प्रवीण कुमार के निर्देशन में उपनिरीक्षक श्री पीयूष चौधरी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, महेश परमार, राकेश सिंह एवं कांस्टेबल प्रदीप द्वारा सुनियोजित एवं सघन तलाशी अभियान संचालित किया गया।

अभियान के दौरान उपलब्ध विवरण के आधार पर संदिग्ध युवक एवं नाबालिग लड़की को चिन्हित कर विधिवत हिरासत में लिया गया। तत्पश्चात की गई पूछताछ में नाबालिग (उम्र 16 वर्ष, निवासी अंधेरी पश्चिम, मुंबई) एवं आरोपी युवक शिवम (उम्र 19 वर्ष, निवासी रायबरेली, उत्तर प्रदेश) द्वारा घर से भागकर आने की पुष्टि की गई।

प्रकरण में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए दोनों को अग्रिम जांच हेतु GRP अहमदाबाद को सुपुर्द किया गया तथा संबंधित वर्सोवा पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने RPF टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनकी त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से नाबालिग की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जो यात्रियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 5461 रुपये और चांदी वायदा में 11586 रुपये की गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा में 1 रुपये का सुधार

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 20 से 26 मार्च के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 6184243.35 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 438856.03 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 5745382.5 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 34289 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में साप्ताहिक आधार पर कुल प्रीमियम टर्नओवर 57155.97 करोड़ रुपये का हुआ।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 438856 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 5745382 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 327531 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34289 पॉइंट के स्तर पर

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 327531.56 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 148302 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 148457 रुपये के उच्च और 129595 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 144954 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 5461 रुपये या 3.77 फीसदी की गिरावट के साथ 139493 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 6059 रुपये या 5.11 फीसदी औंधकर 112479 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 731 रुपये या 4.92 फीसदी गिरकर 14121 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 147598 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 148600 रुपये के उच्च और 129312 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में यह वायदा 4896 रुपये या 3.38 फीसदी लुढ़ककर 140121 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 147499 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 149486 रुपये के उच्च और 129500 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 145452 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 5626 रुपये या 3.87 फीसदी की गिरावट के साथ 139826 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 239948 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 240000 रुपये और नीचे में 199643 रुपये पर पहुंचकर, 231460 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 11586 रुपये या 5.01 फीसदी लुढ़ककर 219874 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 12408 रुपये या 5.24 फीसदी गिरकर 224366 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 12580 रुपये या 5.31 फीसदी औंधकर सप्ताह के अंत में 224399 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में 36272.63 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 9.25 रुपये या 0.83 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1121.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता मार्च वायदा 1.15 रुपये या 0.38 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 307.75 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 2.55 रुपये या 0.77 फीसदी बढ़कर 333 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 6.8 रुपये या 3.65 फीसदी बढ़कर 193.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 74961.54 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 8851 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 9620 रुपये और नीचे में 8072 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 1 रुपये या 0.01 फीसदी के सुधार के साथ 8999 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा बिना बदलाव के 8999 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ही स्थिर रहा। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 292.4 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 297.5 रुपये और नीचे में 268.3 रुपये पर पहुंचकर, 294.5 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 13.4 रुपये या 4.55 फीसदी गिरकर 281.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 13.3 रुपये या 4.52 फीसदी लुढ़ककर 281.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 973.4 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 16.5 रुपये या 1.7 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 989.4 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 224949.13 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 102582.43 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 30371.36 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 3228.71 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 131.15 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2541.41 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 55162.71 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 19660.98 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 2525 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 21229 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 2804 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 29724 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 13894 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 5854 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 15027 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 53662 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15068 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 23269 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 33754 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 35473 के उच्च और 33754 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 28 पॉइंट घटकर 34289 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 13.96 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में नमो लक्ष्मी-नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजनांतर्गत 354 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का डीबीटी से वितरण किया

▸▸ मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया का सीमित उपयोग कर पढ़ाई के लिए अधिक समय देने पर ध्यान केन्द्रित करने की प्रेरणा दी

▸▸ विद्यालय स्तर पर एसएसआईपी अंतर्गत 20 हजार रुपए तक का अनुदान देकर विद्यार्थियों में उद्यमिता के प्रति रुचि विकसित करने का भगीरथ प्रयास : शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा

▸▸ विद्या समीक्षा केन्द्र में एसएसआईपी 2.0, नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मैरिट तथा मुख्यमंत्री ज्ञानसेतु मैरिट स्कॉलरशिप योजनाओं के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वस्पर्शी एवं गुणवत्तायुक्त बनाने के संकल्प के साथ गांधीनगर स्थित विद्या समीक्षा केन्द्र में शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता तथा शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा की प्रेरक उपस्थिति में छात्रवृत्ति वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तथा उपस्थित महानुभावों के करकमलों से एसएसआईपी 2.0, नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मैरिट तथा मुख्यमंत्री ज्ञानसेतु मैरिट स्कॉलरशिप योजना के लगभग 13.96 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 354 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरणा से राज्य में कन्याओं की उच्च शिक्षा का प्रमाण बढ़ाने तथा विज्ञान संकाय के प्रति बेटे-बेटियों का झुकाव बढ़ाने के लिए नमो लक्ष्मी तथा नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना शुरू की गई हैं।

राज्य सरकार ने अब तक 27.61 लाख विद्यार्थियों को इन योजनाओं के तहत 1871.78 करोड़ रुपए की सहायता दी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2001 में जब गुजरात की शासनधुरा संभाली, तब उन्होंने कन्या केळवणी (शिक्षा) महोत्सव तथा शाला प्रवेशोत्सव शुरू करवा कर कन्या शिक्षा की ज्योत जगाने के लिए गाँव-गाँव जाकर शिक्षा की भिक्षा मांगी थी। पूर्व में गुजरात में ड्रॉपआउट रेशियो लगभग 34-38 प्रतिशत था, जो आज घटकर केवल 2 प्रतिशत पर आ गया है। आज राज्य के विद्यालय 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लैबोरेटरी जैसी वर्ल्डक्लास सुविधाओं से सज्ज बने हैं, जिससे विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने लगी है।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि गुजरात के सपूत तथा विश्वनेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'शिक्षित राष्ट्र' के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश के शिक्षा क्षेत्र में भी आमूल परिवर्तन आया है।

बेटियों के सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए श्री पटेल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा आर्थिक स्थिति के कारण अधूरी न रहे; इसके लिए राज्य सरकार ने निरंतर चिंता करते हुए नमो लक्ष्मी तथा नमो सरस्वती विज्ञान साधना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से विद्यालयों में बेटियों की संख्या में 6-7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है।

> **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**
>
> ▸▸ प्रधानमंत्री के भगीरथ प्रयासों के परिणामस्वरूप आज राज्य में बेटियों का ड्रॉपआउट रेशियो घटकर केवल दो प्रतिशत पर पहुँचा
>
> ▸▸ राज्य के विद्यालय 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लैबोरेटरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज
>
> ▸▸ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश के शिक्षा क्षेत्र में भी आमूल परिवर्तन आया
>
> ▸▸ विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से विद्यालयों में बेटियों की संख्या में 6-7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात लगातार पाँच वर्ष से स्टार्टअप रैंकिंग में भी पहले स्थान पर है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा काल से ही इनोवेशन के लिए श्रेष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।

उन्होंने इस संदर्भ में एसएसआईपी 2.0 अंतर्गत विद्यार्थियों के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें प्रोत्साहन सहायता के चेक का वितरण भी किया। ऐसे 735 युवा विद्यार्थियों को कुल 69.69 लाख रुपए की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को वरिष्ठ-ज्येष्ठ समान वात्सल्य भाव से प्रेरणा देते हुए कहा कि छात्र जीवन में सोशल मीडिया का सीमित समय के लिए उपयोग हो और पढ़ाई पर अधिक ध्यान केन्द्रित हो; ऐसा आचरण बच्चों को करना चाहिए। शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने कहा कि मुख्यमंत्री के करकमलों से शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य के 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 354 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि का प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वितरण किया गया, जो इस पारदर्शी सरकार का एक और पारदर्शी कदम है।

डॉ. वाजा ने कहा कि बच्चे को समान तथा विश्व स्तरीय शिक्षा देकर गुजरात विकसित भारत-2047 के सपने को साकार करने के लिए मजबूत आधारस्तंभ बना है। स्टार्टअप यानी उद्यमिता-एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में निरंतर प्रयास है। राज्य के जिन 735 स्टार्टअप इनोवेशन आइडिया का चयन हुआ है और उन पर काम करना है, उन सभी 1400 से अधिक विद्यार्थियों की स्टार्टअप यात्रा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गुजरात ऐसा राज्य बना है, जो स्कूली स्तर पर स्टार्टअप इनोवेशन के आइडिया पर 20 हजार रुपए तक का अनुदान देता है, जिसका मूल उद्देश्य स्कूल से ही विद्यार्थियों में उद्यमिता के प्रति रुचि विकसित करना है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि नमो लक्ष्मी योजना तथा नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के माध्यम से पिछले 2 वर्ष में स्कूल में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस योजना की सफलता दर्शाती है। इस सफलता को ध्यान में लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा आगामी वर्ष में दोनों योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जब गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति आई है, तब शिक्षा केवल अभ्यास नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों का सपना है।

मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ अनेक सकारात्मक तथा परिणामोन्मुखी योजनाओं के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों के अध्ययन तथा जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने जोड़ा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे; इस उद्देश्य से गत वर्ष राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 12708 तथा माध्यमिक विद्यालयों में 9400 शिक्षकों की मेगा भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज स्टार्टअप इकोसिस्टम को गुजरात सरकार विद्यार्थियों के क्लासरूम तक ले गई है, जो नई पीढ़ी के लिए गौरव समान है। शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर स्वागत संबोधन करते हुए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री मिलिंद तोरवणे ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व तथा शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को इनोवेशन एवं मैरिट द्वारा भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में गढ़ने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन विभिन्न योजनाओं का उम्दा उद्देश्य है कि वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' तथा 'विकसित गुजरात' के निर्माण के लिए विद्यार्थी नवीनता तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा से देश सेवा में अपना अमूल्य योगदान दें।

विद्यालय आयुक्तालय के निदेशक श्री रचित राज ने आभार ज्ञापन किया।

एसएसआईपी 2.0 अंतर्गत विभिन्न विद्यार्थियों ने उनके द्वारा किए गए नए इनोवेशन के बारे में अपने प्रतिभाव व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर उत्तर की विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक श्री रंजीत कुमार, शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी सहित प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थी सहभागी हुए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का उत्तराधिकार संबंधित भूमि लेन-देन में स्टाम्प ड्यूटी में राहत देने वाला किसान तथा जन हितकारी निर्णय

▸▸ जंत्री आधारित स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान में राहत देकर 300 रुपए की टोकन स्टाम्प ड्यूटी लेने का किसान-जन हितकारी निर्णय

▸▸ किसानों के लिए खेती की जमीन की उत्तराधिकार संपत्ति की बिक्री में आर्थिक बोझ कम होगा

▸▸ परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे में सरलता आने से विवाद और कोर्ट केस में कमी आएगी

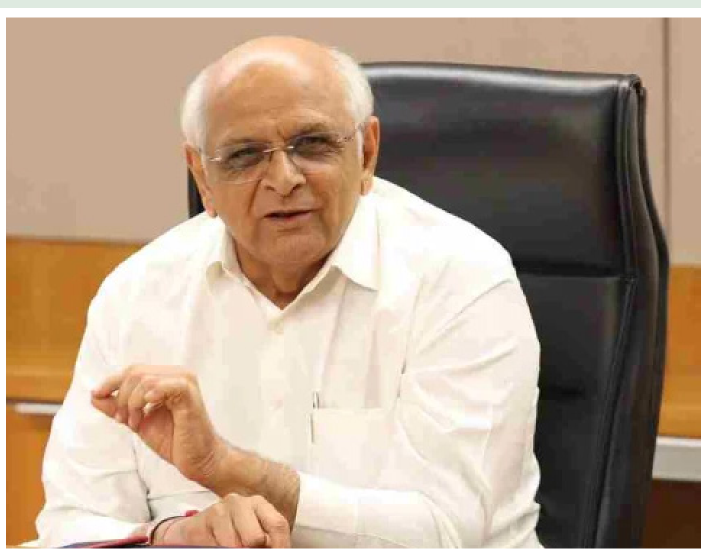

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी और संपार्श्विक उत्तराधिकारी के बीच होने वाले जमीन संबंधी आंतरिक लेन-देन के लिए जंत्री आधारित स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों में राहत देने का जनहितोन्मुखी निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री के समक्ष समाज के विभिन्न अग्रणियों, किसान संघों तथा किसान संगठनों द्वारा की गई प्रस्तुति पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए यह किसान और जन हितकारी निर्णय किया है।

गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 9 के तहत राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी कम करने या माफ करने के प्राप्त अधिकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने खेती की जमीन से संबंधित कुछ मामलों में जंत्री आधारित स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों से राहत देकर 300 रुपए की टोकन स्टाम्प ड्यूटी लागू करने का निर्णय किया है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार उत्तराधिकार प्रविष्टि/प्रविष्टियों के तहत संयुक्त कब्जेदारों में से किसी एक या अधिक उत्तराधिकार (मृत मूल खातेदार के प्रत्यक्ष उत्तराधिकार के मामले में यदि एक भी उत्तराधिकारी जीवित न हो, तो संपार्श्विक उत्तराधिकार) द्वारा अन्य एक या अधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में एक या अधिक चरणों में हक उठाने के मामलों में प्रत्येक हक उठाने/कमी के दस्तावेज पर 300 रुपए स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी।

यदि प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी जीवित हों, तो उनमें से एक या अधिक के नाम एक या अधिक चरणों में दाखिल करने के मामले में, एक भी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी जीवित न हो, तो जीवित संपार्श्विक उत्तराधिकारियों में से एक या अधिक उत्तराधिकारियों के नाम दाखिल करने के मामले में प्रत्येक जीवितता में हक दाखिल करने के दस्तावेज पर 300 रुपए स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी।

समय के क्रमानुसार एक या अधिक चरण में उत्तराधिकार प्रविष्टि/प्रविष्टियों के अंतर्गत दाखिल हुए संयुक्त खातेदारों द्वारा एक या अधिक चरण में बंटवारा किया जाए (ऐसे उत्तराधिकार से प्रत्यक्ष या उसका अस्तित्व न हो, तब संप्राश्विक उत्तराधिकार दाखिल हुआ हो सकता है), तो प्रत्येक बंटवारे के दस्तावेज पर 300 रुपए स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी।

इसके अलावा खेती की जमीनों के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसमें : जिस मामले में एक भी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी जीवित न हो, तो ही संपार्श्विक प्रकार के एक या अधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में एक या अधिक चरणों में हकों को उठाने, जीवन प्रमाणपत्र में नाम/हक दाखिल करने तथा बंटवारे के संबंध में उक्त दर्शाए गए प्रत्येक रूपांतरण दस्तावेज पर 300 रुपए स्टाम्प ड्यूटी वसूली विनियमित करनी होगी।

मुख्यमंत्री के इस जन हितकारी निर्णय के फलस्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति बंटवारा सरल बनने से कोर्ट केस तथा विवादों में कमी आएगी, वैध दस्तावेजीकरण में वृद्धि होगी और हाल में स्टाम्प ड्यूटी अधिक होने से जो कई लेन-देन गैरदस्तावेजी रहते हैं, उनमें इस सुधार के बाद लोग आसानी से पंजीकरण कराएंगे।

इतना ही नहीं, किसानों को खेती की जमीन की उत्तराधिकार संपत्ति की बिक्री में आर्थिक बोझ घटने से बड़ी राहत मिलेगी और पारदर्शिता एवं स्पष्टता का ध्येय साकार होगा। यानी कि अधिकार पत्र (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिक स्पष्ट बनेंगे और भूमि स्वामित्व अधिकार संबंधी भ्रांतियां कम होंगी।

इस 300 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी से प्रक्रिया तेज तथा व्यावहारिक बनेगी और लोगों को लेन-देन में अधिक सरलता होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी।

पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस (20937) के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूचित किया जाता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जयपुर–रेवाड़ी मुख्य रेल खंड पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 95 एवं 106 पर 'कट एंड कवर' विधि से रेल अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण कार्य किया जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उक्त कार्य हेतु दिनांक 10 मई, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 20:00 बजे तक (10 घंटे) का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

उक्त ब्लॉक के कारण दिनांक 09 मई, 2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 20937 पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग फुलेरा–जयपुर–अलवर–रेवाड़ी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी होकर संचालित की जाएगी। इस अवधि के दौरान उक्त ट्रेन जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर एवं खैरथल स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस अस्थायी परिवर्तन को ध्यान में रखें। ट्रेनों के संचालन में संभावित विलंब की स्थिति में यात्री NTES ऐप अथवा भारतीय रेल की आधिकारिक सूचना प्रणालियों जैसे - वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें। पश्चिम रेलवे द्वारा संबंधित यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचना प्रदान की जाएगी।

सूरत नगर निगम के अधिकारियों के यूनियन द्वारा रात में किए गए धरने के खिलाफ पुलिस की निष्क्रियता

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरतः- सूरत नगर निगम के अधिकारियों ने आधी रात को लालगेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थित सूरत नगर निगम भवन में यूनियन कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। इसके विरुद्ध विभिन्न यूनियनों ने 20/11/2025 को लालगेट पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत की जांच सूरत शहर के लालगेट पुलिस क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त को सौंपी गई थी। लेकिन चार महीने बीत जाने के बावजूद जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह सूरत पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाता है। आमतौर पर आम अपराधियों को पकड़ा जाता है, घुमाकर ले जाया जाता है और उनसे लूटपाट की जाती है, लेकिन इस मामले में, मानो कुछ हुआ ही न हो, पुलिस ने कोई जांच नहीं की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूरत नगर निगम में लगभग तीन लाख कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी अपनी शिकायतें एक साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते। कई कर्मचारी सूरत नगर निगम भवन में काम करते हैं। कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण और समाधान के लिए विभिन्न संघ अस्तित्व में आए हैं। सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ, जो ब्रिटिश काल में पंजीकृत था जब महाराष्ट्र और गुजरात एक थे। अखिल भारतीय श्रमिक संगठन, जो 20 वर्ष पूर्व पंजीकृत है। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कांग्रेस, जो महाराष्ट्र में पंजीकृत है। इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बुट्टाजी थे, जिन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों और गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। सरदार बुट्टाजी ने वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए इस संघ की स्थापना की थी। एक अन्य संघ नवयुवन कर्मिक सेवा संघ है, जिसके नेताओं ने कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान किया है। मिली जानकारी के अनुसार, कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने यूनियनों को पूर्व सूचना दिए बिना आधी रात को यूनियन कार्यालयों के ताले तोड़ दिए और रिश्वत के तौर पर जमा की गई धनराशि के साथ-साथ देश के महान नेताओं की तस्वीरें, राष्ट्रपिता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीरों का फ्रेम भी ले गए। इन अधिकारियों ने कर्तव्य का घोर उल्लंघन किया है। उन्होंने देश के महान व्यक्तित्वों का अपमान भी किया है। यदि नगर निगम चाहता तो यूनियन नेताओं की उपस्थिति में कार्यालय खाली करवा सकता था, लेकिन रात 12:00 बजे पुलिस ने यूनियन नेताओं को गेट पर ही रोक दिया और यूनियन कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में किरित जे. वाघेला, मोहम्मद इकबाल शेख, हेमंत जे. सोलंकी और नरेश बी. पदाया द्वारा हस्ताक्षरित शिकायत रेड गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है, जिसमें नगर निगम के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सूरत नगर निगम में कार्यरत लगभग 25 यूनियनों के अनुसार, सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल शेख ने नगर निगम की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त उप आयुक्त निधि सिवाच और आयुक्त शालिनी अग्रवाल के प्रशासन के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में सफाई कर्मचारियों को सफाई उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने में हुई नाइंसाफी का आरोप लगाया गया था। उप आयुक्त निधि सिवाच ने गुजरात उच्च न्यायालय के नोटिस को नजरअंदाज करते हुए लगभग 78 कर्मचारियों को गलत तरीके से पदोन्नत कर दिया। इसके विरोध में गुजरात उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने पर उप आयुक्त निधि सिवाच को उच्च न्यायालय में पेश होकर पदोन्नति के आदेश रद्द करने का निर्देश दिया गया। इससे उप आयुक्त निधि सिवाच का अहंकार आहत हुआ और इन यूनियन नेताओं को सबक सिखाने के लिए उन्होंने, आयुक्त शालिनी अग्रवाल और अन्य लोगों ने आधी रात को यूनियन कार्यालयों के ताले तोड़कर उन पर कब्जा कर लिया। यूनियनें सरकार द्वारा और सरकार की मंजूरी से ही अस्तित्व में आती हैं। तत्कालीन उपायुक्त निधि सिवाच ने सूरत नगर निगम के लगभग 30 हजार कर्मचारियों/अधिकारियों को बिना यूनियन के काम करने का पाप किया है। यहां सवाल उठता है कि गुजरात में कुछ कलेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर निधि सिवाच और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पुलिस को कौन रोक रहा है?

दाहोद से केजरीवाल–मान का गुजरात सरकार पर तीखा प्रहार: आदिवासी किसान और गरीबों के मुद्दों पर घेरा, पंजाब मॉडल का दिया उदाहरण

(जीएनएस)। दाहोद। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके दाहोद में आयोजित 'विजय विश्वास सभा' राजनीतिक रूप से बेहद अहम मंच बन गई, जहां अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने राज्य की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा के दौरान दोनों नेताओं ने आदिवासी समाज, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्याओं को केंद्र में रखते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 30 वर्षों में गुजरात की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आदिवासी समाज सबसे ज्यादा उपेक्षित और शोषित वर्ग बनकर रह गया है। केजरीवाल के अनुसार, आदिवासी क्षेत्रों में न तो शिक्षा की उचित व्यवस्था है और न ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है और गरीब परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं।

उन्होंने मजदूरों की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति भीषण गर्मी में दिनभर मेहनत करता है, लेकिन उसे उचित मजदूरी नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी योजनाओं में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आदिवासी नेता चैतर वसावा को गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के कारण जेल भेजा गया, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है।

किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के किसानों की स्थिति भी बेहद खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर नहीं मिल पाता और कई बार उन्हें महीनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है। सिंचाई के लिए पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इतने वर्षों के शासन के बावजूद सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है।

केजरीवाल ने अपने भाषण में पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी 2022 से पहले हालात कुछ ऐसे ही थे, जहां आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के बीच सत्ता का अदला-बदली चलता रहा। उन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने बदलाव का फैसला किया और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दिया। इसके बाद से राज्य में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे उनकी लागत कम हुई है और आय में सुधार हुआ है। साथ ही, फसल का भुगतान 24 घंटे के भीतर करने की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया गया है और आम लोगों को बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है।

सभा में मौजूद भगवंत मान ने भी गुजरात सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब में जो वादे किए थे, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि चार साल के भीतर ही सरकार ने किसानों, मजदूरों और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

भगवंत मान ने बताया कि पहले पंजाब में भी किसानों को रात में बिजली मिलती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब दिन में 8 घंटे बिजली की नियमित आपूर्ति की जा रही है, जिससे खेती करना आसान हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में 90 प्रतिशत घरों का बिजली बिल शून्य आता है, क्योंकि सरकार ने बिजली को मुफ्त कर दिया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने हर परिवार के लिए 10 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर प्रदान किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बड़े अस्पताल में इलाज करवा सकता है और उसका खर्च सरकार वहन करती है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के खातों में हर महीने आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो पंजाब की तरह यहां भी सभी वादों को पूरा किया जाएगा।

पूरी सभा के दौरान दोनों नेताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति केवल वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि 'गारंटी' पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जनता को अब यह तय करना है कि वह पुराने राजनीतिक ढांचे के साथ रहना चाहती है या फिर एक नए विकल्प को मौका देना चाहती है।

दाहोद की इस सभा ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में गुजरात की राजनीति में मुकाबला और अधिक तीखा होने वाला है। आदिवासी, किसान और आम नागरिकों के मुद्दों को केंद्र में रखकर विपक्ष ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के संकेत दे दिए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों का असर आने वाले चुनावों में किस तरह दिखाई देता है और जनता किस दिशा में अपना समर्थन देती है।

ईंधन पर राहत के संकेत: उत्पाद शुल्क कटौती से पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की उम्मीद, वैश्विक हालात अब भी चुनौती

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई और वैश्विक अस्थिरता के बीच आम जनता को राहत देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की गई है, जिसके बाद आने वाले दिनों में ईंधन की खुदरा कीमतों में कमी की उम्मीद जताई जा रही है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है।

सरकार के इस निर्णय के तहत पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये कर दिया गया है, यानी इसमें 10 रुपये की सीधी कमी की गई है। वहीं डीजल पर यह शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इस कदम का सीधा असर तेल कंपनियों की लागत पर पड़ेगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वे खुदरा स्तर पर कीमतों में कटौती कर सकती हैं और इसका लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।

हालांकि, घरेलू स्तर पर यह राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अब भी चुनौती बनी हुई हैं। खासकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। यह मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन रास्तों में से एक है, और यहां किसी भी तरह की बाधा का असर सीधे भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ता है।

इसी वैश्विक दबाव के चलते घरेलू तेल कंपनियों ने हाल के दिनों में कुछ श्रेणियों के ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी भी की थी। निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Nayara Energy ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, जिससे बाजार में और दबाव देखने को मिला। इससे यह साफ हो जाता है कि केवल सरकारी टैक्स में कटौती ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की दिशा भी कीमतों को तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है।

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका अधिकांश परिवहन समुद्री मार्गों के जरिए होता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक संकट का सीधा असर देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। हालांकि, कुछ टैंकर अब भी भारत पहुंच रहे हैं, जिससे आपूर्ति पूरी तरह बाधित नहीं हुई है, लेकिन अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पाद शुल्क में यह कटौती अल्पकालिक राहत जरूर दे सकती है, खासकर तब जब महंगाई पहले से ही आम लोगों की जेब पर असर डाल रही हो। लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए वैश्विक परिस्थितियों में सुधार जरूरी होगा। यदि कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती रहती हैं या आपूर्ति बाधित होती है, तो घरेलू स्तर पर कीमतों को स्थिर बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।

इसके बावजूद, सरकार का यह कदम बाजार में संतुलन बनाए रखने और महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। इससे न केवल आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वस्तुओं की कीमतों में भी कुछ हद तक कमी आ सकती है।

फिलहाल, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि तेल कंपनियां इस कर कटौती का लाभ कितनी जल्दी और किस स्तर तक उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति किस दिशा में जाती है, यह भी तय करेगा कि यह राहत कितनी स्थायी साबित होगी।